

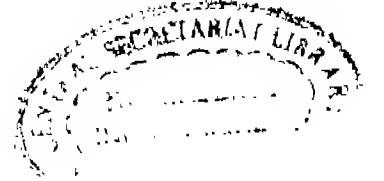


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 65 ]  
No. 65]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 20, 1996/फाल्गुन 30, 1917  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 1996/PHALGUNA 30, 1917

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 350/(पी० एन०)/92—97

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1996

**विषय :—**निर्यात एवं आयात नीति, 1992—97 के पैरा 121 (ङ) के अधीन अभिग्रहित निर्यात लाभों के क्रम में, इन परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक के पीछे हट जाने के परिणामस्वरूप कर्नाटक पावर परियोजनाएं I और II को पूरा करने के लिए कर्नाटक विद्युत बोर्ड (के ई बी)/कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन (केपीसी) को की जाने वाली आपूर्तियों हेतु ।

सं० 3/108/94-आई पी सी-2.—सार्वजनिक सूचना संख्या 321 (पी एन)/92—97, दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

उक्त सार्वजनिक सूचना के उप-पैरा 3(ii) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

“ऊपर कहे अनुसार अभिग्रहित निर्यात नीति के अन्तर्गत लाभों को सुपुर्दगी सारणी की ठेका अवधि के दौरान की गई आपूर्तियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिनमें परियोजना को पूरा करने के लिए परियोजना प्राधिकरण द्वारा सुपुर्दगी सारणी की बढ़ाई गई अवधि भी शामिल होगी ।”

2. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है ।

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 350/(PN)/92—97

New Delhi, the 19th March, 1996

**Subject :** Continuance of deemed export benefits under para 121(e) of the EXIM Policy, 1992—97, for supplies made to Karnataka Electricity Board (KEB)/Karnataka Power Corporation (KPC) for execution of Karnataka Power Projects I and II in the wake of withdrawal of World Bank loan for these projects.

File No. 3/108/94-IPC-II.—Attention is invited to Public Notice No. 321 (PN)/92—97, dt. 26th Oct., 1995.

The Sub-paragraph 3 (ii) of the said Public Notice shall be amended to read as under :—

"The benefits under deemed export policy as stated above, shall be available for supplies made during the contracted period of the delivery schedule which also includes the extended period of delivery schedule by the project authority for execution of the project."

2. This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, Director General of Foreign Trade